नईदुनिया

क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने कहा पड़ोसियों के साथ विवाद सुलझाने को तैयार

तेहरान

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा है कि उनका देश अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत, आपसी समझ और सम्मान के जरिए मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। उन्होंने क्षेत्रीय देशों से सहयोग बढ़ाने और अस्थिरता के कारणों को कम करने का आह्वान किया।

ईरान सरकार की अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी के अनुसार, इराक के पैट्रियटिक यूनियन आफ कुर्दिस्तान (पीयूके) के प्रमुख बाफेल तलबानी के साथ बैठक में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने ईरान और इराकी कुर्दिस्तान के लोगों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण बताया।

पेज़ेशकियन ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल क्षेत्रीय देशों को कमजोर करने और उनके संसाधनों का फायदा उठाने के लिए विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों का मुकाबला करने के लिए क्षेत्र के देशों को आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाना चाहिए।

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि किसी समूह की जायज मांगें हैं, तो ईरान बातचीत और आपसी सम्मान के दायरे में उन मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों से भी अनुचित व्यवहार और अत्यधिक मांगों से बचने की अपील की।

उन्होंने मुस्लिम देशों के बीच साझा धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान सहयोग, बातचीत, निष्पक्षता और न्याय के जरिए किया जा सकता है।

बैठक के दौरान पेज़ेशकियन ने ईरान और इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। वहीं, बाफेल तलबानी ने ईरान को इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र का करीबी मित्र बताते हुए दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। तलबानी ने सीमा सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कुर्दिस्तान क्षेत्र से लगी ईरान की सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और इराक के बीच हुए सुरक्षा समझौते के तहत सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय सरकार-विरोधी समूहों से निपटने और क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तलबानी के साथ एक आर्थिक टीम भी ईरान पहुंची, जिसका उद्देश्य व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना था। तलबानी की ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेज़ाई के साथ भी बैठक हुई।

न्यूज ब्रीफ

ब्रिटेन के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होगा कनाडा

वाशिंगटन। कनाडा ने ब्रिटेन के नेतृत्व वाले जाइंट एक्सपेडिशनरी फोर्स (जेईएफ़) में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है। इसे कनाडा और ब्रिटेन समेत यूरोपीय सहयोगी देशों के बीच रक्षा एवं सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू के मुताबिक, कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के कार्यालय ने बताया कि कार्नी ने जेईएफ़ में शामिल होने के लिए आवेदन की घोषणा की और इस पहल में कनाडा की भागीदारी के लिए ब्रिटेन के समर्थन का स्वागत किया। यह घोषणा ब्रिटेन में कार्नी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम की मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने कनाडा और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। जेईएफ में फिलहाल डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन और ब्रिटेन शामिल हैं। यह गठबंधन मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। बैठक के दौरान कार्नी और बर्नहम ने ग्लोबल काम्बैट एयर प्रोग्राम (जीसीएपी) के जरिए रक्षा-औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। कनाडा जुलाई में इस कार्यक्रम में आब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय ने कनाडा के जीसीएपी में पहला आब्जर्वर देश बनने का भी स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर भी चर्चा हुई।

संयुक्त राष्ट्र को अमेरिका से 72.5 करोड़ डालर मिले, 2027 में मतदान अधिकार सुरक्षित

न्यायार्क। अमेरिकी प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के नियमित बजट में 72.5 करोड़ डालर का भुगतान किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस भुगतान से अमेरिका का बकाया कम हुआ है और वर्ष 2027 में महासभा में उसके मतदान अधिकार पर तत्काल मंडरा रहा खतरा भी टल गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि अमेरिका ने नियमित बजट के लिए 72.5 करोड़ डालर का भुगतान किया। इससे पहले अमेरिका ने शांति अभियानों के लिए भी 10.2 करोड़ डालर का भुगतान किया था। हक के मुताबिक, भुगतान के बाद भी अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट का करीब 1.312 अरब डालर बकाया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि नए भुगतान के कारण अमेरिका 2027 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 19 के तहत मतदान अधिकार खोने की स्थिति में नहीं है। अनुच्छेद 19 के अनुसार, यदि किसी सदस्य देश का बकाया उसके दो वर्षों के देय नियमित योगदान से अधिक हो जाता है तो महासभा में उसका मतदान अधिकार निलंबित किया जा सकता है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान भी है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली और खर्चों पर सवाल उठाते हुए कई एजेंसियों के लिए स्वैच्छिक वित्त पोषण में कटौती की है।

नेपाल के वित्त मंत्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तीन दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे

काठमांडू। नेपाल के वित्त मंत्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तीन दिवसीय भारत दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। वाग्ले की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य आपदा के बाद पुनर्निर्माण सहित दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना है। उनके सचिवालय के अनुसार, यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। वाग्ले भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। वह भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनकी भारतीय विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर से भी मुलाकात निर्धारित है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष जावेद अशरफ द्वारा आयोजित व्यापक बैठक में शामिल होंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के सम्मेलन में वह मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लेंगे।

लाल सागर में तनाव के बीच मस्कट में अमेरिका-हूती के बीच हुई गुप्त बैठक

मस्कट

लाल सागर में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राजनयिकों ने ओमान की राजधानी मस्कट में हूती प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मामले की जानकारी रखने वाले एक क्षेत्रीय सूत्र के मुताबिक, यह बैठक सप्ताहांत में ओमान स्थित अमेरिकी दूतावास में हुई। बैठक में अमेरिका और हूतियों के बीच मई 2025 के युद्धविराम को बनाए रखने और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य को खुला रखने पर चर्चा हुई। अमेरिकी समाचार एजेंसी एक्सिओस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बैठक ओमान सरकार की मदद से आयोजित की गई थी। अमेरिका की कोशिश है कि वह यमन में सऊदी अरब और हूतियों के बीच चल रहे संघर्ष में सीधे सैन्य रूप से शामिल हुए बिना लाल सागर के इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में आवाजाही जारी रखे। वाशिंगटन ने अब तक सऊदी अरब की ओर से सैन्य सहयोग के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया है।

सूत्र ने बताया कि अमेरिका की ओर से बैठक में अमेरिकी दूतावास के राजनयिक शामिल हुए, लेकिन अमेरिकी राजदूत इसमें मौजूद नहीं थे। बैठक के दौरान हूती प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर कहा कि वे अमेरिका के साथ मई 2025 में हुए युद्धविराम को जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि हाल में फिर शुरू हुई उनकी कार्रवाई केवल सऊदी जहाजों को निशाना बना रही है। साथ ही हूतियों ने बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य से अन्य जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखने का आश्वासन भी दिया।

अमेरिकी विदेश विभाग ने बैठक की खबरों पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया। विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रमुख हितों में लाल सागर और क्षेत्र में आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना तथा आतंकवाद के प्रसार को रोकना शामिल है।

प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका यमन को लेकर अपने क्षेत्रीय सहयोगियों और साझेदारों के साथ नियमित संपर्क में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हूतियों और अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ साझा आतंकवाद-रोधी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

बैठक के एक दिन बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका हूतियों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीधे तौर पर हूतियों से बातचीत में शामिल रहा है और प्रशासन का मानना है कि वह स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।

इसी बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल-बुसैदी से क्षेत्रीय तनाव कम करने के प्रयासों को लेकर बातचीत की।

लाल सागर संकट के बीच यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव हाल के दिनों में बढ़ा है। हूतियों की ओर से सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई हैं। इनमें मक्का की दिशा में ड्रोन हमले और सऊदी अरब के अन्य शहरों को निशाना बनाने वाले मिसाइल हमले भी शामिल हैं।

सऊदी अरब ने यमन में हूती ठिकानों के खिलाफ हवाई हमले तेज किए हैं। हालांकि, सऊदी समर्थित यमनी बलों को अब तक जमीन पर हूतियों के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल नहीं हुई है।

हूती विद्रोहियों का अब भी बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास के तटीय क्षेत्रों और कई द्वीपों पर नियंत्रण है। ऐसे में अमेरिका के लिए इस समुद्री मार्ग को खुला रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक प्रमुख शिपिंग रूट है।

मस्कट में हुई बैठक से संकेत मिलता है कि ओमान अमेरिका और हूतियों के बीच संवाद के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। क्षेत्रीय तनाव के बीच अमेरिका के सामने चुनौती यह है कि वह लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही बनाए रखते हुए यमन के संघर्ष में सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बच सके।

अमेरिकी हाउस ने रूस-ईरान पर प्रतिबंध वाला बिल पास किया, भारत-चीन पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ का प्रावधान

वाशिंगटन

अमेरिकी हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस और ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट आफ 2026 को 262-159 मतों से मंजूरी दे दी। बिल अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है।

रूस की अंतरराष्ट्रीय समाचार टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे (आरटी) और तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू के मुताबिक, बिल के समर्थन में 203 रिपब्लिकन और 58 डेमोक्रेटिक सांसदों ने वोट किया, जबकि सात रिपब्लिकन और 152 डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसका विरोध किया। इससे पहले अमेरिकी सीनेट इसे 86-11 के बड़े द्विदलीय बहुमत से पारित कर चुकी है। बिल कानून बनने के बाद राष्ट्रपति को उन देशों से आयात होने वाले सामान पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार मिलेगा, जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल या गैस खरीदते हैं या रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं। इस प्रावधान का असर भारत और चीन पर पड़ने की संभावना को लेकर खास चर्चा है, क्योंकि दोनों देश रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं। हालांकि, बिल में कुछ परिस्थितियों में छूट और टैरिफ से बचने के प्रावधान भी शामिल हैं। प्रस्तावित कानून रूस से जुड़े अधिकारियों, ओलिगार्क्स, उनके परिवार के सदस्यों, विदेशी व्यक्तियों तथा रूसी बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था और यूक्रेन युद्ध को आर्थिक रूप से समर्थन देने वाले नेटवर्क पर दबाव बढ़ाना है। बिल में ईरान के खिलाफ मौजूदा प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने का भी प्रावधान है। इसके तहत ईरान के ऊर्जा और हथियार क्षेत्रों से जुड़े प्रतिबंधों की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बिल का विरोध करने वाले कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने राष्ट्रपति को मिलने वाले व्यापक टैरिफ अधिकारों पर चिंता जताई। उनका तर्क है कि इससे राष्ट्रपति को व्यापार नीति में काफी व्यापक अधिकार मिल सकते हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है।

नेपाल में आई बाढ़ में बहने से 191 वाहन और 344 लोग लापता

काठमांडू। नेपाल के रसुवा जिले में 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के अंतर्गत आने वाले 191 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ में इन वाहनों के चालक, सहचालक और यात्रियों समेत 344 लोग लापता हैं। महासंघ के महासचिव डेकनाथ गौतम के अनुसार, बाढ़ से देशभर की नौ यातायात कंपनियों के वाहन प्रभावित हुए हैं। नेपाल अरनिको यातायात सेवा प्राइवेट लिमिटेड की 19 बस, एक मिनीट्रक, दो जीप और चार कंटेनर बाढ़ में बह गए हैं, जबकि 50 मजदूर लापता हैं। इसी तरह पासाड़ ल्हामु यातायात प्राइवेट लिमिटेड, बालाजु की 19 बसें और 21 लोग लापता हैं। भक्तपुर न्यू विजन यातायात प्राइवेट लिमिटेड के दो कंटेनर मलबे में दबने से दो चालक लापता हैं। हिमालयन यातायात कंपनी के चार ट्रक, 16 कंटेनर और एक सुमो वाहन बह गए हैं और 10 चालक लापता हैं। वहीं, नेपाल टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समिति के सात टिपर, 22 कंटेनर, 23 ट्रक और एक ट्रेलर बाढ़ के मलबे में दब गए हैं, जबकि 45 चालक लापता हैं।

करीब 5 हजार रोहिंग्याओं की वापसी को मंजूरी, म्यांमार से बातचीत करेंगे मलेशियाई पीएम

कुआलालंपुर

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि वह म्यांमार के सैन्य शासन के प्रमुख से राष्ट्रपति बने मिन आंग ह्लाइंग को आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित करेंगे। इस दौरान मलेशिया हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों की म्यांमार वापसी के मुद्दे पर बातचीत करेगा।

अनवर ने कहा कि मलेशिया और म्यांमार की मौजूदा सरकार को औपचारिक मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन शरणार्थियों की वापसी जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए म्यांमार के साथ संवाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित और चरणबद्ध वापसी का रास्ता निकाला जा सकता है।

अनवर के मुताबिक, म्यांमार ने करीब 5,000 शरणार्थियों की वापसी को मंजूरी दी है। उनकी वापसी का खर्च मलेशिया उठाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि शुरुआती चरण के बाद अन्य शरणार्थियों की वापसी भी चरणबद्ध तरीके से संभव होगी।

मलेशिया ने इससे पहले कहा था कि स्वैच्छिक वापसी कार्यक्रम के पहले चरण के तहत सितंबर में करीब 1,500 म्यांमार शरणार्थियों को वापस भेजने की योजना है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) के अनुसार, म्यांमार लौटना रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए अभी सुरक्षित नहीं माना जाता।

मिन आंग ह्लाइंग ने 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता संभाली थी। अप्रैल में राष्ट्रपति बनने के बाद से वह विदेश यात्राओं और आधिकारिक दौरों के जरिए अपनी सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

अनवर ने कहा कि मलेशिया पहले म्यांमार की सैन्य सरकार का मुखर आलोचक रहा है और संघर्ष रोकने से इनकार करने पर उसने कई बार निराशा जताई है। हालांकि, अब शरणार्थियों की वापसी के लिए म्यांमार के साथ व्यावहारिक बातचीत की जरूरत है।

मिन आंग ह्लाइंग हाल के महीनों में लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के अलावा चीन, भारत और रूस का भी दौरा कर चुके हैं। मलेशिया की यात्रा होने पर वह आसियान के 11 सदस्य देशों में से पांचवें देश का दौरा करेंगे।

रोहिंग्या म्यांमार का एक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय है। बड़ी संख्या में रोहिंग्या लंबे समय से म्यांमार से भागकर पड़ोसी देशों में शरण लेते रहे हैं। बांग्लादेश में दस लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जबकि मलेशिया में भी बड़ी संख्या में म्यांमार से आए शरणार्थी मौजूद हैं।

अनवर ने रोहिंग्या समुदाय की परेशानियों को स्वीकार करते हुए कहा कि मलेशिया उन्हें स्थायी रूप से अपने यहां नहीं रख सकता। उनका कहना है कि समाधान के लिए म्यांमार से बातचीत और कूटनीति जरूरी है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले अमेरिका-फिलिस्तीन तनाव बढ़ा, वीजा प्रतिबंधों का ऐलान

वाशिंगटन

न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की शुरुआत से कुछ दिन पहले अमेरिका ने फिलिस्तीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि फिलिस्तीन लिबरेशन आर्गनाइजेशन (पीएलओ) के सदस्यों और फिलिस्तीनी अथारिटी (पीए) के अधिकारियों के लिए वीजा प्रतिबंधों को आगे भी जारी रखा जाएगा।

तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने कांग्रेस को बताया कि पीएलओ और पीए अमेरिकी कानूनों के तहत किए गए अपने वादों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में फिर से विफल रहे हैं। विभाग ने इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनी पक्ष की कई कार्रवाइयों का हवाला दिया।

अमेरिका ने विशेष रूप से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) और इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस (आईसीजे) के माध्यम से इजरायल-फिलिस्तीन विवाद को अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तक ले जाने की कोशिशों का उल्लेख किया।

अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, फिलिस्तीनी पक्ष की ओर से फिलिस्तीनी राज्य को एकतरफा अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने के प्रयास भी बातचीत की प्रक्रिया को दरकिनार करने की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं।

अमेरिका ने पीएलओ और पीए पर आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगाए हैं।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया सत्र अगले सप्ताह न्यूयार्क में शुरू होने वाला है। पिछले साल भी अमेरिका ने महासभा से पहले पीएलओ और पीए के अधिकारियों के वीजा को मंजूरी देने से इनकार किया था या कुछ वीजा रद्द किए थे।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते के तहत न्यूयार्क स्थित फिलिस्तीनी मिशन को कुछ विशेष छूट प्राप्त है।

पिछले साल फिलिस्तीनी अथारिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास व्यक्तिगत रूप से महासभा में शामिल नहीं हो सके थे और उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए सभा को संबोधित किया था।

अमेरिकी विदेश विभाग की डिप्टी प्रवक्ता पालोमा चाकान ने कहा कि ट्रंप प्रशासन हर वीजा फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा निर्णय मानता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मेजबान देश के तौर पर अमेरिका अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता है, लेकिन वीजा आवेदकों की जांच और सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा।

चाकान के मुताबिक, महासभा में शामिल होने वाले प्रतिनिधिमंडलों को वीजा आवेदन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में पहले ही जानकारी दी गई थी। यदि कोई आवेदक सुरक्षा जांच के मानकों या अन्य निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करता है, तो उसका वीजा अस्वीकार किया जा सकता है।

अमेरिका की घोषणा पर फिलिस्तीनी अथारिटी या पीएलओ की ओर से तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति महमूद अब्बास और आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने वाले फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल के प्रत्येक सदस्य के वीजा आवेदन पर क्या फैसला लिया गया है।

अमेरिकी विदेश विभाग का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है।